[2015] 4 एस. सी. आर 108

श्रीमती प्रियंका श्रीवस्तव और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2012 की आपराधिक अपील सं. 781)

19 मार्च, 2015

[न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 156 (3)––शक्ति, दायरे के तहत—उधारकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 जिसने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की और जिसके खिलाफ सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, उसने बैंक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए— उधारकर्ता और बैंक अधिकारियों ने विभिन्न मामलों को वापस लेने की शर्त के साथ एकमुश्त समझौता किया– उधारकर्ता ने बैंक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए धारा 156(3) के तहत एक और आवेदन दायर किया था और उस शिकायत में एफआईआर दर्ज की गई थी– ओटीएस में कर्जदार ने उक्त एफआईआर के बारे में खुलासा नहीं किया– अपीलकर्ता-बैंक अधिकारी उच्च न्यायालय ग— — माना गया: एफआईआर रद्द होने योग्य है– प्रतिवादी संख्या 3 का उद्देश्य केवल ऋण के भुगतान से बचने के इरादे से अपीलकर्ताओं को परेशान करना था—धारा 156(3)-सरफेसी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से पहले सुरक्षित लेनदारों या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान के प्रति दंडाधिकारी को खुद को सचेत रखना चाहिए था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित:

1. जब सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले वित्तीय संस्थान का कोई उधारकर्ता सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत एक अलग प्रक्रिया भी है, जिसमें अधिक सावधानी, सतर्कता और चौकसी का रवैया अपनाया जाना चाहिए। "आवेदन के अनुसार" एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी करना समाज में एक बहुत ही अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा करता है और दंडाधिकारी के गलत दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यह वित्तीय संस्थानों को घुटनों पर लाने के लिए अदालतों के साथ साहसिक कदम उठाने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 जैसे बेईमान और सिद्धांतहीन वादियों को भी प्रोत्साहित करता है। प्रतिवादी संख्या 3 ने पहले के बैंक अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था और उच्च न्यायालय द्वारा समझौता दर्ज करने वाली एक रिट याचिका में मामला निपटाए जाने के बाद, उसने आपराधिक मामला वापस नहीं लिया और किसी ऐसी स्थिति का इंतजार किया जहां वह प्रतिशोध ले सके। अपीलकर्ता संख्या 1 के कार्यकाल के दौरान, जो वर्तमान में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, न तो लोन लिया गया, न ही चूक की गई और न ही सरफेसी एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की गई। हालाँकि, दूसरी बारी में अपीलकर्ता नंबर 1 के कहने पर सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। प्रतिवादी नंबर 3 का शैतानी मंसूबा ऋण के भुगतान से बचने के एकमात्र इरादे से अपीलकर्ताओं को परेशान करना था। [पैरा 24, 25 और 26] [132-एफ-एच; 133-ए-सी]

2. धारा 156(3) के तहत शक्ति न्यायिक बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता दर्शाती है। यह सीआरपीसी की धारा 154 के स्तर पर कदम उठा रही पुलिस नहीं है। कोई वादी अपनी मर्जी से दंडाधिकारी के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। साफ-सुथरे हाथों वाले एक सैद्धांतिक और वास्तव में दुखी नागरिक को उक्त शक्ति का आह्वान करने की सुलभ पहुंच होनी चाहिए। यह नागरिकों की रक्षा करती है, लेकिन जब विकृत

मुकदमेबाजी अपने साथी नागरिकों को परेशान करने के लिए इस रास्ते को अपनाती है, तो उसे रोकने और उस पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसदेश में एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. आवेदनों को आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहता है। इसके अलावा, एक उपयुक्त मामले में, दंडाधिकारी को सच्चाई की जांच करने की सलाह दी जाएगी और वह आरोपों की सत्यता की जांच भी कर सकता है। यह शपथ पत्र आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। इस तरह के आवेदन नियमित तरीके से बिना किसी जिम्मेदारी के केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यह तब और अधिक परेशान करने वाला और चिंताजनक हो जाता है जब कोई ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है जो वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं, जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ लेने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई हिसाब बराबर करने पर आमादा हो। धारा 156(3) के तहत याचिका दायर करते समय धारा 154(1) और 154(3) के तहत पूर्व आवेदन करना होगा। आवेदन में दोनों पहलुओं को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए और इस आशय के आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाने चाहिए। यह निर्देश कि धारा 156(3) के तहत एक आवेदन को एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए उसे धारा 156(3) के तहत दंडाधिकारी के प्राधिकार का लापरवाही से उपयोग करने से रोकेगा। इसके अलावा, मामले के आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसकी सत्यता को दंडाधिकारी द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है। धारा 156(3)-सरफेसी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से पहले सुरक्षित लेनदारों या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान के प्रति दंडाधिकारी

को खुद को सचेत रखना चाहिए था। [पैरा 26, 27 और 30] [133-एफ-एच; 134-ए-जी; 135-ई]

मनहरिभाई मुलजीभाई काकाडिया और अन्य बनाम शैलेशभाई मोहनभाई पटेल और अन्य 2012 (8) एससीआर 1015: (2012) 10 एससीसी 517; *देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य बनाम वी नारायण रेड्डी और अन्य* 1976 (0) पूरक एससीआर 524: (1976) 3 एससीसी 252; *अनिल कुमार बनाम एम.के. अयप्पा* 2013 (9) एससीआर 869: (2013) 10 एससीसी 705; *दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य* (2007) 12 एससीसी 496; *सीआरईएफ फाइनेंस लिमिटेड बनाम श्री शांति होम्स (प्राइवेट) लिमिटेड* 2005 (2) पूरक एससीआर 873: (2005) 7 एससीसी 467; *रामदेव फ़ूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य* 16.03.2015 को निर्धारित आपराधिक अपील संख्या 600/2007; *ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार* (2014) 2 एसईसी 1––पर भरोसा किया गया।

निर्णय विधि संदर्भ

2012 (8) एससीआर 1015	संदर्भित किया गया	पैरा 4
1976 (0) पूरक एससीआर 524	संदर्भित किया गया	पैरा 18
2013 (9) एससीआर 869	संदर्भित किया गया	पैरा 19
2007 (12) एससीसी 496	संदर्भित किया गया	पैरा 20
2005 (2) पूरक एससीआर 873`	संदर्भित किया गया	पैरा 21
2014 (2) एससीसी 1	संदर्भित किया गया	पैरा 23

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की आपराधिक अपील सं. 781

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2011 की विविध आपराधिक रिट याचिका सं. 24561 में दिनांक 23.12.2011 के निर्णय और आदेश से।

अजय कुमार, सुदीप डे अपीलार्थियों की ओर से।

विक्रांत यादव, गौरव ढींगरा, आशुतोष शर्मा सुनील कुमार जैन, कौशिक चौधरी, आकर्ष गर्ग उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

1. वर्तमान अपील एक ऐसे परिदृश्य को प्रस्तुत और चित्रित करती है जो न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि इसमें एक हलचल पैदा करने की क्षमता भी है जो किसी को परेशान अवस्था में यह विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है कि कैसे कुछ बेईमान, सिद्धांतहीन और पथभ्रष्ट मुकदमेबाज अदालत के दरवाजे खटखटाने के लिए लापरवाही भरे तरीके से सरलता और नवीनता से योजना तैयार कर सकते हैं, मानो, यह एक प्रयोगशाला है जहां विविध प्रयोग हो सकते हैं और ऐसे कुशल व्यक्ति आवेदन में किए गए कठोर दावों द्वारा पीड़ा के कैनवास को चित्रित करके अपनी मर्जी और इच्छा से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सकते हैं, यद्यपि वास्तविक इरादा बिना किसी दूरस्थ पश्चाताप के वैधानिक प्राधिकारियों को परेशान करना है, आविष्कारी उद्देश्य के साथ मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप में उक्त अधिकारियों पर मानसिक दबाव बनाना है, क्योंकि वे आपराधिक मामले में सामना करने के लिए कानून की अदालत में घसीटा जाना पसंद नहीं करेंगे, और उनपर इस तरह से और दबाव डाला जाए कि जिस वित्तीय संस्थान का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, वह अंततः "एकमुश्त निपटान" के अनुरोध को इस उम्मीद के साथ स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाए कि जिन जिद्दी डिफॉल्टरों ने उससे पैसा उधार लिया था, वे उनके खिलाफ शुरू किए गए मामलों को वापस ले लेंगे। जैसे-जैसे हम व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तथ्य सुस्पष्ट रूप से प्रकट होंगे कि कैसे ऐसे व्यक्ति, दिखावटी रूप से पीड़ित लेकिन संभावित रूप से खतरनाक, इसे प्राप्त करने के लिए आत्म-विश्वासपूर्ण महारत के तरीकों को अपनाते हैं। यह दुखद और

दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यात्मक हिसाब है जो इस मामले का आधार बनता है, और, हम दर्द के साथ इसका वर्णन करते हैं।

2. जिन तथ्यों को बताने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि प्रतिवादी नंबर 3, अर्थात्, प्रदीप कुमार बजाज के पुत्र, प्रकाश कुमार बजाज ने 21 जनवरी, 2001, को वित्तीय संस्थान, अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) से आवास ऋण खाता संख्या IHL-583 द्वारा आवासीय ऋण लिया था। ऋण प्रतिवादी नंबर 3 और उसकी पत्नी ज्योत्सना बजाज के नाम पर लिया गया था। चूंकि किश्तों के लगातार भुगतान में चूक हुई थी, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) माना गया था। वित्तीय संस्थान के अधिकारियों ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उधारकर्ताओं को नोटिस जारी किया, (संक्षेप में, 'सरफेसी अधिनियम') और उक्त अधिनियम में की गई कार्यवाही के अनुसरण में, पीएनबीएचएफएल ने 5 जून, 2007 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए जिला दंडाधिकारी, वाराणसी, यूपी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।

3. इस समय, प्रतिवादी नंबर 3 ने 2007 के WP नंबर 44482 को प्राथमिकता दी, जिसे 14 सितंबर, 2007 को उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि इसमें याचिकाकर्ता के लिए अपेक्षित आपत्ति दर्ज करने और उसके बाद, करने का विकल्प खुला था। सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत यथापरिकल्पित उचित कार्रवाई करें। इस समय, प्रतिवादी नंबर 3 ने 2007 की रिट याचिका संख्या 44482 को प्राथमिकता दी, जिसे 14 सितंबर, 2007 को उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि इसमें याचिकाकर्ता के लिए अपेक्षित आपत्ति दर्ज करना और उसके बाद सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत यथापरिकल्पित उचित कार्यवाही करना उपलब्ध था। उपरोक्त टिप्पणी के साथ रिट याचिका खारिज होने के बाद,

प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा, संभवतः आत्म-केंद्रित सोलोमन के ज्ञान के विचार का पोषण करते हुए, वीएन सहाय, संदेश तिवारी और वीके खन्ना, तत्कालीन उपाध्यक्ष, सहायक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के धारा 163, 193 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 200 के तहत 2008 का आपराधिक शिकायत मामला संख्या 1058 दर्ज किया गया। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपियों ने जानबूझकर उसे क्षति पहुंचाने के लिए कदम उठाया है। विद्वान दंडाधिकारी ने 4 अक्टूबर, 2008 के आदेश के तहत आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया और धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने और धारा 202 सीआरपीसी के तहत गवाहों की जांच करने के बाद संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

4. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी नंबर 3 ने 2008 की एक पुनरीक्षण याचिका संख्या 460 को प्राथमिकता दी, जिसे अंततः विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वाराणसी, यूपी द्वारा सुना गया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तथ्यों पर विचार करने और पुनरीक्षणकर्ता की दलीलों पर ध्यान देने के बाद, 4 अक्टूबर, 2008 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ भेज दिया कि वह शिकायत को फिर से सुनेंगे और उक्त आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार संज्ञान आदेश पारित करेंगे। विदित हो कि, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 3 के वकील और राज्य के विद्वान वकील को सुना, लेकिन आरोपी व्यक्तियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। आम तौर पर, हमने इसका उल्लेख नहीं किया होता क्योंकि अपील में यह विषय वस्तु है, लेकिन केवल इस बात को उजागर करने के लिए कि इस प्रकार के मुकदमों से कैसे निपटा जा रहा है और यह भी दिखाने के लिए कि उत्तरदाताओं में अदालतों का रुख करने का अनुचित उत्साह है, ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। उस समय उक्त आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पारित आदेश एक प्रतिकूल आदेश था चूंकि

मामला शिथिल कर दिया गया था। उत्तरदाताओं को सुनना अनिवार्य था, हालांकि वे आरोपी व्यक्ति नहीं बने थे। *मनहारीभाई मुलजीभाई काकाडिया और अन्य बनाम शैलेशभाई मोहनभाई पटेल और अन्य*[1] में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राय दी है कि एक शिकायत याचिका से उत्पन्न मामला जब वरिष्ठ न्यायालय पहुंचता है और एक प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो एक सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रासंगिक अंश यहां पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> "46..... यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर देता है, तो सवाल यह है कि क्या शिकायत में अपराध का आरोपी व्यक्ति शिकायत को खारिज करने के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन में सुनवाई के अधिकार का दावा कर सकता है। संसद इस कानूनी स्थिति से अवगत है कि धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी होने तक आरोपी/संदिग्ध कार्यवाही के किसी भी चरण में सुनवाई के हकदार नहीं हैं, फिर भी संहिता की धारा 401(2) में प्रावधान है कि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए, जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर जब तक कि उसे अपने बचाव में व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा सुनवाई का अवसर न मिले, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
>
> xxxxx xxxxx xxxxx
>
> 48. ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 203 के तहत शिकायत को धारा 200 के चरण में ही खारिज कर दिया गया है या धारा

202 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच पूरी होने पर या पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई भी व्यक्ति जिसे शिकायत में आरोपों की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश जारी किया गया था, ऐसे खारिज किए जाने का प्रभाव शिकायत की कार्यवाही को समाप्त करना है। धारा 401 की उपधारा (2) को सीधे तौर पर पढ़ने पर यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायत में जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत में अपराध करने का आरोप लगाया गया है और धारा 203 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत खारिज कर दी गई है, उसे सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कोई प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। धारा 203 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत को खारिज करना– हालांकि यह प्रारंभिक चरण में है– फिर भी उन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत में कार्यवाही समाप्त हो जाती है जिन पर अपराध करने का आरोप है। एक बार जब शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश के समक्ष संहिता की धारा 401(2) के आधार पर पुनरीक्षण याचिका में ऐसे आदेश को चुनौती दी जाती है, तो संदिग्धों को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है हालाँकि ऐसा आदेश उनकी भागीदारी के बिना पारित किया गया था। धारा 401(2) के तहत "अभियुक्त" या "अन्य व्यक्ति" को उसके पक्ष में लागू होने वाले आदेश का बचाव करने के लिए पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का जो अधिकार दिया गया है, उसे धारा 200, 202, 203 और 204 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। शिकायत को खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाले शिकायतकर्ता के कहने पर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका में, जो

चीजें हो सकती हैं उनमें से एक मजिस्ट्रेट के आदेश को उलटना और शिकायत को पुनर्जीवित करना है। इस मामले में यह दृष्टिकोण है कि आरोपी या अन्य व्यक्ति को संहिता की धारा 401(2) में निहित स्पष्ट प्रावधान के आधार पर सुनवाई से वंचित नहीं किया जा सकता है। चरण महत्वपूर्ण नहीं है चाहे वह प्रक्रिया से पहले का चरण हो या प्रक्रिया के बाद का चरण हो।

xxxxx xxxxx xxxxx

53. हम इस न्यायालय द्वारा पी. सुंदरराजन[2], रघु राज सिंह रौशा[3] और ए. एन. संथानम[4] में व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हैं। हम मानते हैं, जैसा कि होना ही चाहिए, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी जाती है जिसमें धारा 203 के तहत शिकायत को धारा 200 के तहत चरण में या पालन करने के बाद संहिता की धारा 202 के तहत विचाराधीन प्रक्रिया के अनुसार खारिज कर दिया जाता है, अभियुक्त या वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का संदेह है, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई का हकदार है। दूसरे शब्दों में, जहां मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर दिया गया है, शिकायतकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका में उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देने पर, जिन व्यक्तियों को शिकायत में आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है, उन्हें ऐसी पुनरीक्षण याचिका में सुनवाई का अधिकार है। यह संहिता की धारा 401(2) की स्पष्ट आवश्यकता है। यदि पुनरीक्षण न्यायालय शिकायत को खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को पलट देता है

और शिकायत को मजिस्ट्रेट की फाइल में बहाल कर दिया जाता है और इसे नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया जाता है, तो जिन व्यक्तियों पर शिकायत में अपराध करने का आरोप लगाया गया है, उन्हें प्रक्रिया जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वे मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी प्रकार की सुनवाई के हकदार हैं।"

यद्यपि वर्तमान विवाद अलग है, हमने उक्त पहलू से निपटा है क्योंकि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि न्यायालयों ने इस तरह के मामले को कैसे निपटाया और संबोधित किया है ताकि प्रतिशोध की भावना से उधार लेने वाला अंततः अपनी मनमानी का प्रदर्शन कर सके।

5. जैसे वर्णन आगे बढ़ता है, वापिस लौटाने के बाद, विद्वान दंडाधिकारी ने 13 जुलाई, 2009 के आदेश के तहत संज्ञान लिया और वीएन सहाय, संदेश त्रिपाठी और वीके खन्ना को समन जारी किया। उक्त आरोपी व्यक्तियों ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय ने 2010 के आपराधिक विविध संख्या 13628 में 27 मई, 2013 के आदेश द्वारा इस प्रकार फैसला सुनाया:

"प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर की गई शिकायत का अवलोकन यह भी इंगित करता है कि मुद्दे कथित दुर्भावना के आधार पर प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ बैंक अधिकारियों की कार्रवाई के संबंध में थे और इस तरह आईपीसी की धारा 166/500 के तहत एक अपराध बनता था। दोनों धाराएं गैर संज्ञेय और जमानती हैं और प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय हैं। उपरोक्त कारणों से 482 की याचिका स्वीकार की जानी चाहिए और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर

आपराधिक शिकायत, 2009 का शिकायत मामला संख्या 1058, रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन स्वीकार किया जाता है और अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायालय संख्या 2 वाराणसी के न्यायालय में लंबित 2009 की आपराधिक शिकायत मामला संख्या 1058, प्रकाश कुमार बजाज बनाम पी.एन.बी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और अन्य को रद्द किया जाता है।"

6. वर्तमान समय में हमें कुछ समय के लिए बैठने की आवश्यकता है। अंतराल अवधि में उधारकर्ताओं ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(3 ए) के तहत आपत्ति दर्ज की। विदित हो, चूंकि आपत्ति का निपटारा नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी नंबर 3 ने 2009 की रिट याचिका संख्या 22254 को प्राथमिकता दी, जिसे 5 मई, 2009 को उच्च न्यायालय ने निपटाने का निर्देश देते हुए निस्तारण कर दिया। अंततः, सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2009 के आदेश द्वारा आपत्ति को खारिज कर दिया गया। अस्वीकृति के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 3 ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), इलाहाबाद, यूपी के समक्ष 2010 की प्रतिभूतिकरण अपील संख्या 5 दायर की, जिसे 23 नवंबर, 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। डीआरटी के समक्ष सफलता न मिलने के कारण उधारकर्ताओं को ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी), इलाहाबाद, यूपी के समक्ष अपील करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

7. इस स्तर पर, यह कहना उचित होगा कि तीसरे प्रतिवादी, अगर हम खुद को ऐसा कहने की अनुमति देते हैं, तो संभवतः उन्होंने उन अधिकारियों के मन में डर की भावना पैदा करने में महारत हासिल कर ली है जो आपराधिक मामलों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पिछली कार्यवाही को रद्द करने के बाद, अक्टूबर, 2011 में तीसरे प्रतिवादी ने वीएन सहाय, संदेश त्रिपाठी और वीके खन्ना के

खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक और आवेदन दायर किया, जिसमें आपराधिक साजिश रचने और तीन पोस्ट-डैटिड चेकों का हवाला देते हुए दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप लगाया गया और अंततः इसे शिकायत मामला संख्या 344/2011 के रूप में क्रमांकित किया गया, जिसने धारा 465, 467, 468, 471, 386, 506, 34 और 120 बी आईपीसी के तहत 2011 की एफआईआर संख्या 262 को जन्म दिया। इससे संतुष्ट नहीं होने पर, 30.10.2011 को, उन्होंने वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 156 (3) के तहत एक और आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि संपत्ति का कम मूल्यांकन किया गया है। इसे शिकायत मामला संख्या 396/2011 के रूप में क्रमांकित किया गया था, जिसमें विचारण दंडाधिकारी ने एसएचओ को वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश के क्रम में एफआईआर संख्या 298/2011 दर्ज की गई।

8. इस समय, यह बताना जरूरी है कि तीसरे प्रतिवादी ने अधिकारियों को एकमुश्त निपटान के लिए सहमत किया। उक्त समझौता इस शर्त के साथ हुआ था कि एकमुश्त निपटान की स्वीकृति पर वह अपने द्वारा दायर विभिन्न मामलों को वापस ले लेगा। जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलेगा, तीसरे प्रतिवादी ने शिकायत मामले संख्या 344/2011 और 396/2011 की शुरुआत के बारे में खुलासा नहीं किया। 28.11.2011 को, एकमुश्त निपटान पर कार्रवाई की गई और तीसरे प्रतिवादी ने 15 लाख रुपये जमा किए। इस स्तर पर, यह उल्लेख करना उचित है कि वीएन सहाय और दो अन्य ने रिट (सी) संख्या 17611/2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीआरएल विविध संख्या 13628/2010 में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन के साथ मामले की सुनवाई की। हमने पहले ही उसमें पारित आदेश का प्रासंगिक भाग पुनः प्रस्तुत कर दिया है। विदित हो कि, रिट याचिका का निपटारा भी उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार करते हुए किया गया है:

"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मनीष त्रिवेदी, प्रतिवादी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव और विद्वान एजीए को सुना गया।

विद्वान एजीए द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में जांच पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, उसी पर विचार करते हुए, यह याचिका निरर्थक हो गई है।

अंतरिम आदेश दिनांक 2.12.2011 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

तदनुसार, इस याचिका का निपटारा किया जाता है।"

10. इस मोड़ पर, हम अतीत को फिर से देखने के लिए बाध्य हैं। प्रतिवादी ने, जैसा कि पहले कहा गया है, डीआरएटी के समक्ष अपील की थी। उक्त अपील को 2013 की अपील संख्या 5 के रूप में क्रमांकित किया गया था। उक्त अपील में, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, उधारकर्ता द्वारा 15.00 लाख रुपये की राशि के दावे का निपटान करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव को बैंक ने अपने पत्र दिनांक 15.11.2011 द्वारा स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता ने पूरी राशि भी जमा कर दी, जिसके लिए समझौता हुआ यानी 15.00 लाख रुपये। इसके बाद, अपीलकर्ता की शिकायत यह थी कि चूंकि निपटान की पूरी राशि अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की जा चुकी है, इसलिए बैंक को स्वामित्व विलेख वापस करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्वामित्व विलेख वापस नहीं किया गया था।

ट्रिब्यूनल का विचार था कि चूंकि मामला सुलझ चुका है, इसलिए, प्रतिभूतिकरण आवेदन को निरर्थक मानकर खारिज कर दिया गया और ट्रिब्यूनल ने स्वामित्व विलेख की वापसी के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया। इसलिए, अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2011 से व्यथित होकर वर्तमान अपील दायर की है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब समझौते के तहत पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो प्रतिवादी-बैंक स्वामित्व विलेख को वापस करने के लिए बाध्य था, जो अपीलकर्ता को वापस नहीं किया गया है।

प्रतिवादी-बैंक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि समझौता दिनांक 14.11.2011 के पत्र द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसमें इस शर्त का उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता शिकायत मामले को वापस ले लेगा जो उसने आपराधिक न्यायालय के समक्ष दायर किया है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें शिकायत मामले को वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वामित्व विलेख अपीलकर्ता को वापस किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी-बैंक द्वारा आज से सात दिनों के भीतर अपीलकर्ता को स्वामित्व विलेख वापस कर दिया जाएगा और उसके बाद, अपीलकर्ता आपराधिक मामला संख्या 1058/09 को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर करेगा जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वाराणसी के समक्ष लंबित है।"

11. प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा बनाई गया कुरूपतापूर्ण भंवरजाल यहीं समाप्त नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल होने की अथक भावना थी। प्रतिवादी नंबर 3 ने वर्तमान अपीलकर्ताओं, जो क्रमशः उपाध्यक्ष और मूल्यांकनकर्ता हैं, के खिलाफ 30 अक्टूबर, 2011 को विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया था। याचिका के मुख्य भाग में, जैसा कि हम अनुच्छेद 19 और 20 में पाते हैं, इसे इस प्रकार कहा गया है:

> "उपरोक्त मामला स्पीड पोस्ट के माध्यम से पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी को भेजा गया था लेकिन उस संबंध में आज तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। उक्त अभियुक्त द्वारा किया गया उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 465, 467, 471, 386, 504, 34 एवं 120 बी आईपीसी के दायरे में आता है और इस प्रकार संज्ञेय अपराध बनता है और भलीभांति सिद्ध होता है।"

12. उपरोक्त आवेदन के आधार पर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वाराणसी, यूपी ने संबंधित पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट मांगी और जानकारी प्राप्त की कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और इसलिए, स्थानीय पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस प्रकार टिप्पणी की:

> "आवेदक द्वारा आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवेदक का कथन है कि उसने भुगतान के लिए वित्तीय बैंक को पहले ही 3 पोस्टडेटेड चेक दिए थे और वित्तीय सोसायटी में पोस्टडेटेड चेक उपलब्ध होने के बावजूद ऋण खाते में एक भी शेयर का भुगतान नहीं कराया गया है। विपक्षीगण जानबूझकर प्रार्थी के विरूद्ध षड़यंत्र

एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भुगतान हेतु पूर्व उल्लेखित पोस्टडेटेड चेक जमा नहीं कर रहे हैं तथा ये लोग प्रार्थी की बहुमूल्य सम्पत्ति को हड़पने का षडयंत्र कर रहे हैं। एक आपराधिक षड़यंत्र के तहत अवैध एवं झूठे एवं मनगढ़ंत आधार पर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वाराणसी के समक्ष याचिका दाखिल की गई है, जो संज्ञेय अपराध के दायरे में आता है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संज्ञेय अपराध का मामला बनता प्रतीत होता है और इसकी जांच पुलिस से कराना न्यायसंगत होगा।"

इतना कहने के बाद इसे इस प्रकार निर्देशित किया गया:

"आवेदन के आलोक में, SHO भेलपुर, वाराणसी को मामला दर्ज करने और इसकी जांच करने का निर्देश दिया जाता है।"

13. उपरोक्त आदेश के आधार पर, 2011 की एफआईआर संख्या 298 दर्ज की गई, जिसने धारा 465, 467 और 471 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2011 की अपराध संख्या 415 को जन्म दिया। उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने 2011 की आपराधिक विविध संख्या 24561 में उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने एक गूढ आदेश में कहा कि एफआईआर के अवलोकन पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। इस दृष्टिकोण के चलते उसने आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अत: यह अपील विशेष अनुमति द्वारा।

14. सुनवाई के दौरान, यूपी राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जांच एजेंसी 21 नवंबर, 2012 को पहले ही अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। उक्त रिपोर्ट इस प्रकार है:

"वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता बार-बार बुलाने के बाद भी किसी भी जांचकर्ता के सामने उपस्थित नहीं हुआ है। और वह श्रीमती की कार्रवाई. प्रियंका श्रीवास्तव ने 'अच्छे विश्वास' में अपने कानूनी अधिकारों के अनुसार काम किया है, जो सरफेसी अधिनियम की धारा 32 के तहत संरक्षित है। उपरोक्त जांच के साथ, वर्तमान रिपोर्ट समाप्त हो गई है।"

15. पूछे जाने पर, राज्य के विद्वान वकील का तर्क था कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अजय कुमार ने प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अंतिम प्रारूप/अंतिम रिपोर्ट को खारिज करके रिपोर्ट को स्वीकार करने का विकल्प है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ सकते हैं या शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सकते हैं, जो विरोध याचिका दायर करने का हकदार है और उसके बाद, मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसलिए, इस न्यायालय को योग्यता के आधार पर विवाद को संबोधित करना चाहिए और कार्यवाही को रद्द करना चाहिए।

16. हमने तथ्यों को विस्तार से बताया है क्योंकि वर्तमान मामला, जैसा कि हम पाते हैं, सीआरपीसी की धारा 156(3) का सहारा लेने का बहुत बड़े पैमाने पर उदाहरण देता है, जैसे कि, यह एक नियमित प्रक्रिया हो। इसके अलावा, सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही और अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम उक्त अधिनियम के तहत उच्च मंच के समक्ष चुनौती योग्य है, और यदि, किसी उधारकर्ता को आपराधिक कानून का सहारा लेने की अनुमति दी जाती है, जिस तरह से लिया गया है, तो यह बताने के लिए कोई विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने की अंतर्निहित क्षमता है। यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है कि वैधानिक उपायों को चतुराई से दरकिनार कर दिया गया है और व्यक्तिगत

अधिकारियों के बीच भय पैदा करने के लिए अभियोजन का रास्ता अपनाया गया है, जिससे उन्हें एकमुश्त निपटान के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके, जिसे वित्तीय संस्थान ने संभवतः स्वीकार नहीं किया होगा। इसके अलावा, शिकायत वापस लेने की सहमति के बावजूद, कम से कम सद्भावना दिखाने के लिए इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके विपरीत विकृत परपीड़क मनोवृत्ति के साथ प्रतिस्पर्धा की गई है। शिकायतकर्ता अभियोजन वापस ले सकता था या नहीं, यह अलग बात है। तथ्य यह है कि कोई प्रयास नहीं किये गये।

17. विद्वान दंडाधिकारी ने, जैसा कि हमने पाया, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आरोपों को सुनाया और इसके बाद बिना कोई विवेक लगाए आवेदन में उल्लिखित अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्वान दंडाधिकारी पर लगाए गए कर्तव्य को हाशिए पर नहीं रखा जा सकता है। इसके वास्तविक अभिप्राय को समझने के लिए, हम उक्त प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

> "156. संज्ञेय मामले की जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
> –– कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी दंडाधिकारी के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय XIII के उपबंधों के अधीन है।
>
> (2) ऐसे किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया

जाएगा कि मामला ऐसा था जिसकी जांच करने के लिए ऐसे अधिकारी को इस धारा के तहत अधिकार नहीं था।

(3) धारा 190 के तहत अधिकार प्राप्त कोई भी मजिस्ट्रेट उपरोक्तानुसार ऐसी जांच का आदेश दे सकता है।"

18. सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की गई शक्ति की प्रकृति से निपटते हुए, *देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य बनाम वी. नारायण रेड्डी और अन्य*[2] मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ को इस प्रकार व्यक्त करना पड़ा:

"आगे यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 156 की उप-धारा (3) के तहत दिया गया एक आदेश, धारा 156 (1) के तहत जांच की अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पुलिस को एक अनिवार्य अनुस्मारक या सूचना की प्रकृति में है। इस तरह की जांच में पूरी सतत प्रक्रिया शामिल होती है जो धारा 156 के तहत साक्ष्य एकत्र करने से शुरू होती है और धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट या आरोपपत्र के साथ समाप्त होती है।"

19. *अनिल कुमार बनाम एम.के. अयप्पा*[3] में, दो जजों की पीठ को यह कहना पड़ा:

"सीआरपीसी की धारा 156(3) का दायरा कई मामलों में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। मकसूद सैय्यद [(2008) 5 एससीसी 668] में इस अदालत ने धारा 156(3) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से पहले दंडाधिकारी द्वारा विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता की जांच की और माना कि जहां धारा 156(3) या धारा 200 सीआरपीसी के तहत दायर शिकायत पर

क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है, दंडाधिकारी को अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है, ऐसे मामले में, विशेष न्यायाधीश/दंडाधिकारी किसी वैध मंजूरी आदेश के बिना किसी लोक सेवक के खिलाफ धारा 156(3) के तहत मामले को संदर्भित नहीं कर सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का प्रयोग आदेश में प्रतिबिंबित होना चाहिए। केवल यह कथन कि उसने शिकायत, दस्तावेजों का अध्ययन किया है और शिकायतकर्ता को सुना है, जैसा कि आदेश में दर्शाया गया है, पर्याप्त नहीं होगा। शिकायत, दस्तावेजों को देखने और शिकायतकर्ता को सुनने के बाद, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने के लिए दंडाधिकारी ने क्या निर्णय लिया, उसे आदेश में दर्शाया जाना चाहिए, हालांकि उनके विचारों की विस्तृत अभिव्यक्ति की न तो आवश्यकता है और न ही यह वांछनीय है। हमने विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पहले ही निकाल लिया है, जिसमें, हमारे विचार से, जांच का आदेश देने का कोई कारण नहीं बताया गया है।"

20. *दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य*[4] में, इस न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनाया:

"18. ...11. इसलिए स्पष्ट स्थिति यह है कि कोई भी न्यायिक दंडाधिकारी, अपराध का संज्ञान लेने से पहले, संहिता की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो उसे शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच नहीं करनी है क्योंकि वह किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले रहा था। पुलिस को जांच शुरू करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से दंडाधिकारी के पास पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार है। ऐसा करने

में कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। आख़िरकार एफआईआर के पंजीकरण में केवल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी गई पुस्तक में संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी के सार को दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल होती है जैसा कि संहिता की धारा 154 में दर्शाया गया है। भले ही कोई दंडाधिकारी संहिता की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देते समय इतने शब्दों में नहीं कहता है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, यह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए संज्ञेय अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करे क्योंकि वह पुलिस अधिकारी उसके बाद ही संहिता के अध्याय XII में बताए गए आगे के कदम उठा सकता है।"

21. *सीआरईएफ फाइनेंस लिमिटेड बनाम श्री शांति होम्स (पी) लिमिटेड*[5] में, न्यायालय ने अपराधों का संज्ञान लेने वाले दंडाधिकारी की शक्ति से निपटते समय राय दी है कि शिकायत पर विचार करने के बाद, मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत शिकायत को जांच के लिए पुलिस को भेजना उचित समझ सकता है। और फिर:

"जब एक दंडाधिकारी को कोई शिकायत मिलती है तो वह उस पर संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है यदि शिकायत में कथित तथ्य किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं। मामले में दंडाधिकारी के पास विवेकाधिकार है। यदि शिकायत को पढ़ने पर, वह पाता है कि उसमें लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं और धारा 156(3) के तहत जांच के लिए पुलिस को शिकायत अग्रेषित करना न्याय के लिए अनुकूल होगा और जिस मामले की जांच करना मुख्य रूप से पुलिस का कर्तव्य था, उसकी जांच करने में

मजिस्ट्रेट के बहुमूल्य समय को बर्बाद होने से बचाएगा, अपराध का स्वयं संज्ञान लेने के विकल्प के रूप में उसके द्वारा उस मार्ग को अपनाया जाना उचित होगा। जैसा कि पहले कहा गया है, संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत के मामले में, धारा 190(1)(ए) के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले धारा 156(3) के तहत शक्ति का इस्तेमाल मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। हालाँकि, यदि वह एक बार इस तरह का संज्ञान लेता है और अध्याय XV में सन्निहित प्रक्रिया को अपनाता है, तो वह पूर्व-संज्ञान चरण में वापस लौटने और धारा 156(3) का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है।"

22. *हाल ही में, रामदेव फ़ूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य*[6] मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्ति के प्रयोग से निपटते हुए, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि:

"...धारा 156(3) के तहत निर्देश दंडाधिकारी द्वारा विवेक प्रयोग में लिए जाने के बाद ही जारी किया जाना है। जब दंडाधिकारी संज्ञान नहीं लेता है और प्रक्रिया को स्थगित करना आवश्यक नहीं समझता है और मामले को तुरंत आगे बढ़ाने के लिए बनता पाया जाता है, तो उक्त प्रावधान के तहत निर्देश जारी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जहां उपलब्ध जानकारी की विश्वसनीयता के कारण, या न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए सीधे जांच को निर्देशित करना उचित माना जाता है, वहां ऐसा निर्देश जारी किया जाता है। ऐसे मामले जहां दंडाधिकारी संज्ञान लेते हैं और प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर देते हैं, ऐसे मामले होते हैं जहां दंडाधिकारी को अभी भी "आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार के अस्तित्व" का निर्धारण करना है।

23. इस स्तर पर, हम इस संबंध में *ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार*[7] मामले में संविधान पीठ ने जो कहा है, उसका उल्लेख उपयोगी रूप से कर सकते है। बड़ी पीठ ने निम्नलिखित दो प्रश्न रखे थे:-

> "(i) क्या एफआईआर का तुरंत पंजीकरण न करने से पुलिस द्वारा हेरफेर की गुंजाइश बनती है जो पीड़ित/शिकायतकर्ता के आरोप लगाए जाने पर तुरंत शिकायत की जांच करने के अधिकार को प्रभावित करती है; और
>
> (ii) क्या ऐसे मामलों में जहां शिकायत/सूचना स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करती है लेकिन एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाती है तो क्या यह किसी आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन करता है।"

पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बड़ी बेंच ने इस प्रकार राय दी:

> "49. नतीजतन, संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी से संज्ञेय अपराध का खुलासा होना चाहिए। यदि किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली कोई भी जानकारी धारा 154(1) की आवश्यकता को पूरा करने वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष पेश की जाती है, तो उक्त पुलिस अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में उसके सार को दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, अर्थात ऐसी जानकारी के आधार पर मामला दर्ज करना। संहिता की धारा 154 का प्रावधान अनिवार्य है और संबंधित अधिकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी के आधार पर मामला दर्ज

करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, संहिता की धारा 154(1) के स्पष्ट शब्दों को उनका शाब्दिक अर्थ देना होगा। "करेगा

xxx xxx xxx xxx

72. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि एफआईआर का पंजीकरण अनिवार्य है और यह भी कि प्रत्येक एफआईआर को एक अद्वितीय वार्षिक संख्या देकर एफआईआर बुक में दर्ज किया जाना है ताकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ही सक्षम न्यायालय, जहां प्रत्येक एफआईआर की प्रतियां भेजी जानी आवश्यक हैं, द्वारा प्रत्येक पंजीकृत एफआईआर की सख्त निगरानी की जा सके।

xxx xxx xxx xxx

111. संहिता पुलिस को जांच से पहले और बाद में किसी मामले को बंद करने की शक्ति देती है। एक पुलिस अधिकारी संहिता की धारा 157 के तहत जांच से पहले एक एफआईआर को बंद कर सकता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि इसकी जांच करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह धारा स्वयं कहती है कि एक पुलिस अधिकारी तब जांच शुरू कर सकता है जब उसके पास "किसी अपराध के घटित होने पर संदेह करने का कारण" हो। इसलिए, संहिता की धारा 157 के तहत जांच शुरू करने की आवश्यकताएं संहिता की धारा 154 के तहत आवश्यकता से अधिक हैं। पुलिस अधिकारी, किसी दिए गए मामले में, मामले की जांच भी कर सकता है और फिर मामले को बंद करने के अनुसरण में संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर कर सकता है। इसलिए, पुलिस हर एफआईआर में जांच शुरू करने के लिए

उत्तरदायी नहीं है जो संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाती है।

xxx xxx xxx xxx

115. हालाँकि, हम स्पष्ट शब्दों में मानते हैं कि संहिता की धारा 154 सभी संज्ञेय अपराधों की प्राप्ति पर एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण को बताती है, फिर भी, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां अपराधों की उत्पत्ति और नवीनता में परिवर्तन के कारण समय के बीतने के साथ प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा ही एक उदाहरण डॉक्टरों की ओर से चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित आरोपों का है। केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी चिकित्सीय पेशेवर पर मुकदमा चलाना अनुचित और अन्यायी होगा।"

इतना कहने के बाद संविधान पीठ ने आगे यह कहा कि जहां प्रारंभिक जांच आवश्यक है, यह प्राप्त जानकारी के सत्यापन या अन्यथा के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। इतना कहने के बाद, बड़ी पीठ ने कहा:-

"120.6 किस प्रकार की और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार है:

(ए) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद

(बी) वाणिज्यिक अपराध

(सी) चिकित्सीय लापरवाही के मामले

(डी) भ्रष्टाचार के मामले

(ई) ऐसे मामले जहां आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी/चूक होती है, उदाहरण के लिए, देरी के कारणों को संतोषजनक ढंग से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी। उपरोक्त केवल दृष्टांत हैं और उन सभी स्थितियों का विस्तृत विवरण नहीं है जिनके लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है।

120.7. अभियुक्तों और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित और संरक्षित करते हुए प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में 7 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की देरी के तथ्य और इसके कारणों को सामान्य डायरी प्रविष्टि में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए"

हमने उपरोक्त घोषणा का उल्लेख इस उद्देश्य से किया है कि कुछ परिस्थितियों में पुलिस को प्रारंभिक जांच करने की भी आवश्यकता होती है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।

24. उपरोक्त कानून के प्रतिपादन के संबंध में, यह दोहराने की आवश्यकता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट को लगाए गए आरोपों और आरोपों की प्रकृति के संबंध में सतर्क रहना होगा और उचित विवेक का उपयोग किए बिना निर्देश जारी नहीं करना होगा। उसे यह भी ध्यान में रखना होगा कि मामले को भेजना न्याय के लिए अनुकूल होगा और फिर वह अपेक्षित आदेश पारित कर सकता है। वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें आरोपी व्यक्ति बैंक में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। हम इस बात से पूरी तरह परिचित हैं कि पद कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन, विद्वान मजिस्ट्रेट को आरोपों की संपूर्णता, घटना की तारीख और क्या दूर से

कोई संज्ञेय मामला बनता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब सरफेसी अधिनियम के तहत आने वाले वित्तीय संस्थान का उधारकर्ता, सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत एक अलग प्रक्रिया भी है, जिसमें अधिक सावधानी, एहतियात और समझदारी बरतने के दृष्टिकोण का पालन करना होगा।

25. "आवेदन के अनुसार" एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी करना समाज में एक बहुत ही अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा करता है और विद्वान दंडाधिकारी के गलत दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यह प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् प्रकाश कुमार बजाज जैसे बेईमान और सिद्धांतहीन वादियों को भी वित्तीय संस्थानों को घुटनों पर लाने के लिए अदालतों के साथ साहसिक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसा कि तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है, उसने पहले के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था और मामले को उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में समझौता दर्ज करने के बाद निपटाया गया था, वह आपराधिक मामला वापस नहीं लेता है और किसी प्रकार की स्थिति की प्रतीक्षा करता है जहां वह प्रतिशोध ले सकता है मानो वह उन सभी का सम्राट है जिसका वह सर्वेक्षण करता है। दिलचस्प बात यह है कि अपीलकर्ता नंबर 1, जो वर्तमान में उपाध्यक्ष के पद पर है, के कार्यकाल के दौरान न तो ऋण लिया गया, न ही डिफॉल्ट किया गया, न ही सरफेसी अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई की गई। हालाँकि, सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई दूसरी बार में वर्तमान अपीलकर्ता नंबर 1 के कहने पर की गई थी। हम केवल ऋण के भुगतान से बचने के एकमात्र इरादे से अपीलकर्ताओं को परेशान करने के प्रतिवादी नंबर 3 के शैतानी मंसूबे के बारे में बता रहे हैं। जब कोई नागरिक किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेता है, तो यह उसका दायित्व है कि वह वापस भुगतान करे और चूक ना करे या उस मामले में लापरवाही न बरतें। जैसा कि हमने देखा है, वह इस तरह दुस्साहस करने में सक्षम है क्योंकि उसे

यह दृढ़ विश्वास है कि उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन अदालत में जांच एजेंसी को एक निर्देश जारी करने के लिए एक सरल आवेदन है। हमें अवगत कराया गया है कि धारा 154(3) का अनुपालन दिखाने के लिए एक दस्तावेज़ की कार्बन कॉपी दायर की गई है, यह दर्शाता है कि इसे संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया है।

26. इस स्तर पर यह कहना प्रतीत होता है कि धारा 156(3) के तहत शक्ति में न्यायिक विवेक के प्रयोग की आवश्यकता होती है। कानून की एक अदालत शामिल है. धारा 154 के स्तर पर पुलिस कदम नहीं उठा रही है। कोई वादी अपनी मर्जी से दंडाधिकारी के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। साफ-सुथरे हाथों वाले एक सैद्धांतिक और वास्तव में पीड़ित नागरिक को उक्त शक्ति का आह्वान करने की मुक्त पहुंच होनी चाहिए। यह नागरिकों की रक्षा करता है, लेकिन जब विकृत मुकदमेबाज़ी अपने साथी नागरिकों को परेशान करने के लिए इस रास्ते को अपनाती हैं, तो उसे खत्म करने और उस पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

27. हमारी सुविचारित राय में, इस देश में एक ऐसा चरण आ गया है जहां धारा 156(3) सीआरपीसी के आवेदनों को मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक उपयुक्त मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सच्चाई को सत्यापित करने की सलाह दी जाएगी और वह आरोपों की सत्यता को भी सत्यापित कर सकता है। यह शपथ पत्र आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इस तरह के आवेदन नियमित तरीके से बिना किसी जिम्मेदारी के केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यह तब और अधिक परेशान करने वाला और चिंताजनक हो जाता है जब कोई ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है जो वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं, जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती

दी जा सकती है। लेकिन आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ लेने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई हिसाब बराबर करने पर आमादा हो। हमने पहले ही संकेत दिया है कि धारा 156(3) के तहत याचिका दायर करते समय धारा 154(1) और 154(3) के तहत पूर्व आवेदन करना होगा। आवेदन में दोनों पहलुओं को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए और इस आशय के आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाने चाहिए। यह निर्देश देने की आवश्यकता है कि धारा 156(3) के तहत आवेदन को एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए ताकि आवेदन करने वाला व्यक्ति सचेत रहे और यह भी देखने का प्रयास करे कि कोई गलत हलफनामा नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार हलफनामा झूठा पाए जाने पर, वह कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। यह उसे धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार का लापरवाही से इस्तेमाल करने से रोकेगा। इसके अलावा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामले के आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसकी सत्यता को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है। हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि राजकोषीय क्षेत्र, वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले और ऐसे मामले जहां आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी/चूक होती है, से संबंधित कई मामले हैं, जैसा कि ललिता कुमारी में दर्शाया गया है, दाखिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा, विद्वान मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के बारे में भी पता होगा।

28. वर्तमान लिस को दूसरे कोण से देखा जा सकता है। हम थोड़ा आश्चर्यचकित हैं कि वित्तीय संस्थान को विवाद निपटाने के लिए मजबूर किया गया है और हम यह भी सोचते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिकायती मामले दायर किए गए थे। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।

29. इस समय, हम सार्थक रूप से सरफेसी अधिनियम की धारा 32 का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

"32. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.-

इस अधिनियम के तहत सद्भावना से किए गए या छोड़े गए किसी भी कार्य के लिए सुरक्षित ऋणदाता या उधारकर्ता के किसी भी अधिकार का प्रयोग करने वाले किसी भी सुरक्षित ऋणदाता या उसके किसी अधिकारी या प्रबंधक के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।"

30. वर्तमान मामले में, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से पहले खुद को उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सचेत रखना चाहिए था। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद ने अपने विवेक से सुरक्षित ऋणदाताओं या अपने किसी अधिकारी की सुरक्षा के लिए ऐसा प्रावधान किया है, और विधायी जनादेश को ध्यान में रखना होगा।

31. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं और 2011 के अपराध संख्या 298, पुलिस स्टेशन, भेलूपुर, जिला वाराणसी, यूपी में दर्ज मामले में एफआईआर के पंजीकरण को रद्द करते हैं।

32. हमारे द्वारा पारित आदेश की एक प्रति इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा सभी उच्च न्यायालयों के विद्वान मुख्य न्यायाधीशों को भेजी जाएगी ताकि उच्च न्यायालय इसे विद्वान सत्र न्यायाधीशों के बीच प्रसारित कर सकें, जो बदले में इसे विद्वान दंडाधिकारियों के बीच प्रसारित करेंगे ताकि वे धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय अधिक सतर्क और सावधान रह सकें।

अपील की अनुमति दी गई।

देविका गुजराल

[1] (2012) 10 एससीसी 517

[2] (1976) 3 एससीसी 252

[3] (2013) 10 एससीसी 750

[4] (2007) 12 एससीसी 496

[5] (2005) 7 एससीसी 467

16.03.2015 को निर्णित 2007 की आपराधिक अपील संख्या 600

[7] (2014) 2 एससीसी 1

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।